

 **Hindustan Times**

NHRC NOTICE TO 3 STATES' DGPs OVER ATTACK ON JOURNOS

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) of India, on Wednesday, took suo motu cognisance of reported attacks on three journalists in Kerala, Manipur, and Tripura.

According to a statement, the incidents occurred on August 30 this year in Kerala and Manipur, and on September 21 in Tripura. The Commission has issued notices to the Director Generals of Police (DGPs) of the three states, seeking detailed reports on the incidents within two weeks.

In Tripura, the journalist was reportedly assaulted by a group of miscreants armed with sticks and sharp weapons while attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara area of West Tripura.

In Manipur, a journalist was injured after being shot twice with an air gun while covering a flower festival in Senapathi district. In Kerala, a journalist was allegedly attacked by a group of people while returning from a wedding function near Thodupuzha.

In all three cases, the victims were hospitalised and police reportedly registered First Information Reports (FIRs). The NHRC has sought updates from the state police chiefs concerned on the progress of investigations and the steps taken to ensure the safety of journalists.

HTC

buzz

NHRC's National Conference comes up with several suggestions

The National Human Rights Commission (NHRC), India organised a National Conference on 'Human Rights for Prison Inmates' in New Delhi. During the discussions, a lot of valuable suggestions came up on rehabilitation of prisoners, de-congestion of jails, encouraging correctional services, improving the mental health of prisoners, addressing the issues related to women prisoners and their children and de-addiction. Justice V Ramasubramanian chaired the conference.

नोएडा में करंट लगने से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 अक्टूबर।

गौतमबुद्धनगर जिले में बुधवार को हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

पुलिस ने बताया कि यह घटना थाना दनकौर क्षेत्र के कस्बा दनकौर की है और मृतक की पहचान 25 वर्षीय वसीम के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि 35 वर्षीय तौहिद और वसीम गिल्ली डंडा खेल रहे थे और उनकी गिल्ली पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के घर की छत पर चली गई, जिसे लेने के लिए तौहिद पड़ोसी की छत पर गया और वहां से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, उसे बचाने के लिए वसीम भी छत पर पहुंचा और उसे भी करंट लग गया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे दोनों व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डाक्टरों ने वसीम को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तौहिद की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

जनसत्ता

Thu, 23 October 2025

<https://epaper.jansatta.com/c/78396516>



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इंटरशिप

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(एनएचआरसी) की ओर से इंटरशिप
प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।

एनएचआरसी की पहल

इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के छात्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। आवेदक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों-जैसे मानवाधिकार में पीजी डिप्लोमा या एमए, राजनीति विज्ञान या एलएलबी आदि में नामांकित होने चाहिए। छात्रों को बारहवीं और उसके बाद के डिग्री कार्यक्रमों में न्यूनतम 65 फीसदी अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। साथ ही, आवेदकों की आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस इंटरशिप में मानवाधिकारों के संबंध में व्यावहारिक अनुभव पाने का मौका मिलेगा। आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/4cbbe7pw पर जाकर इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एनएचआरसी ने केरल, मणिपुर और त्रिपुरा में तीन पत्रकारों पर हुए कथित हमलों का लिया स्वतः संज्ञान

एनएचआरसी ने तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किया, दो सप्ताह में मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 30 अगस्त, 2025 को केरल और मणिपुर तथा 21 सितंबर, 2025 को त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर तीन पत्रकारों पर हुए हमले के बारे में मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने तीनों मामलों में तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, त्रिपुरा में एक पत्रकार पर कुछ बदमाशों ने लाठियों और धारदार हथियारों से उस समय हमला किया जब वह पश्चिमी त्रिपुरा के हेजामारा

इलाके में एक राजनीतिक दल के वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली गई। मणिपुर में सेनापथी जिले के लाई गांव में एक पुष्प उत्सव की कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर हमला किया गया। उन्हें एयर गन से दो बार गोली मारी गई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। केरल में, थौदुपुझा के पास मंगटुकवाला पहुंचने पर एक पत्रकार पर लोगों के एक समूह ने हमला किया। वह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों ही मामलों में पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं।

पत्रकारों पर हमले को लेकर एनएचआरसी ने तीन राज्यों के डीजीपी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, (विप्र)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को कहा कि उसने पिछले दो महीनों में तीन पत्रकारों पर कथित हमले की खबरों को लेकर केरल, मणिपुर और त्रिपुरा के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने तीन मामलों पर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा, 30 अगस्त को केरल और मणिपुर में तथा 21 सितंबर को त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तीन पत्रकारों पर हमले के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है। तीनों मामलों में एनएचआरसी ने पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी

कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। त्रिपुरा में पत्रकार पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया था। हमला तब किया गया जब वह पश्चिमी त्रिपुरा के हेजामारा इलाके में एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसमें कहा गया है कि उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। मणिपुर के सेनापति जिले के लाई गांव में एक पुष्प उत्सव की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार पर कथित तौर पर हमला किया गया। बयान में कहा गया है कि उन्हें एयर गन से दो बार गोली मारी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

NHRC takes suo motu cognisance of attacks on journalists in Kerala, Manipur, Tripura

GK News Service

New Delhi, Oct 22

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports regarding separate attacks on journalists in Kerala, Manipur, and Tripura, and issued notices to the Directors General of Police of the three states seeking detailed reports within two weeks.

According to reports, a journalist in Tripura was assaulted by miscreants armed with sticks and sharp weapons during a clothes distribution event in Hezamara, West Tripura, and his motorcycle was stolen. In Manipur, another journalist was shot twice with an air gun while covering a flower festival in Laii Village, Senapati district. In Kerala, a journalist was attacked near Mangattukavala in Thodupuzha while returning from a wedding. All three journalists were hospitalised following the assaults, and police have registered cases in each incident.

NHRC notice to 3 DGPs over attack on journos

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) of India, on Wednesday, took suo motu cognisance of reported attacks on three journalists in Kerala, Manipur, and Tripura.

According to a statement, the incidents occurred on August 30 this year in Kerala and Manipur, and on September 21 in Tripura. The Commission has issued noti-

ces to the Director Generals of Police (DGPs) of the three states, seeking detailed reports on the incidents within two weeks.

In Tripura, the journalist was reportedly assaulted by a group of miscreants armed with sticks and sharp weapons while attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara area of West Tripura.

HTC

NHRC issues notices to DGPs of 3 States over attacks on journalists

NEW DELHI, Oct 22: The National Human Rights Commission today said it has issued notices to police chiefs of Kerala, Manipur and Tripura over reports of alleged attacks on three journalists in the past two months.

In a statement, the NHRC said it has sought detailed reports on the three cases in two weeks.

The commission has "taken suo moto cognisance of media reports about the attacks on three journalists at different places, in Kerala and Manipur on August 30, and in Tripura on September 21," it said.

In all three cases, the NHRC has issued notices to the Director Generals of Police, seeking detailed reports.

The journalist in Tripura was allegedly assaulted by a

group of people with sticks and sharp weapons while he was attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also stolen, it said.

The journalist in Manipur was allegedly attacked while reporting on a flower festival in Laii village of Senapathi district. He was shot twice with an air gun, causing severe injuries, the statement said.

In Kerala, a journalist was allegedly assaulted by a group of people when he reached Mangattukavala near Thoudupuzha. He was returning from a wedding function.

In all three cases, the victims were reportedly hospitalised for treatment and cases were registered by the police, it added. – PTI

पत्रकारों पर हुए हमलों का मामला एनएचआरसी ने राज्यों के डीजीपी को नोटिस भेजकर 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 30 अगस्त को केरल और मणिपुर तथा 21 सितंबर को त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर तीन पत्रकारों पर हुए हमले के बारे में स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने तीनों मामलों में तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। त्रिपुरा में एक पत्रकार पर कुछ बदमाशों ने लाठियों और धारदार हथियारों से उस समय हमला किया जब वह पश्चिमी त्रिपुरा के हेजामारा इलाके में एक राजनीतिक दल के वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। उनकी मोटर साइकिल भी चोरी कर ली गई।



मणिपुर में सेनापथी जिले के लाई गांव में एक पुष्प उत्सव की कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर हमला किया गया। उन्हें एयर गन से दो बार गोली मारी गई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। केरल में, थौदुपुझा के पास मंगडुकवाला पहुंचने पर एक पत्रकार पर लोगों के एक समूह ने हमला किया। वह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों ही मामलों में पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं।

NHRC.NIC

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported attacks on three journalists in Kerala, Manipur and Tripura

Press release

National Human Rights Commission

<https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-attacks-on-three-journalists-in-kerala,-manipur-and-tripura>

New Delhi: 22nd October, 2025

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported attacks on three journalists in Kerala, Manipur and Tripura

Issues notices to the Director Generals of Police of the three states, calling for detailed reports on the matters within two weeks

The National Human Rights Commission, (NHRC) India, has taken suo motu cognizance of media reports about the attack on three journalists at different places in Kerala and Manipur on 30th August, 2025 and Tripura on 21st September, 2025. In all three cases, the Commission has issued notices to the Director Generals of Police of the three states, calling for detailed reports on the matters within two weeks.

Reportedly, the journalist in Tripura was assaulted by a group of miscreants with sticks and sharp weapons while he was attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also stolen.

The journalist in Manipur was attacked while covering a flower festival in Laii Village of Senapathi District. He was shot twice with an air gun causing severe injuries.

In Kerala, the journalist was assaulted by a group of people when he reached Mangattukavala near Thoudupuzha. He was returning from a wedding function. Reportedly, in all three cases, the victims were hospitalised for treatment and cases were registered by the police.

PIB

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported attacks on three journalists in Kerala, Manipur and Tripura

Issues notices to the Director Generals of Police of the three states, calling for detailed reports on the matters within two weeks

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2181499>

Posted On: 22 OCT 2025 3:37PM by PIB Delhi

The National Human Rights Commission, (NHRC) India, has taken suo motu cognizance of media reports about the attack on three journalists at different places in Kerala and Manipur on 30th August, 2025 and Tripura on 21st September, 2025. In all three cases, the Commission has issued notices to the Director Generals of Police of the three states, calling for detailed reports on the matters within two weeks.

Reportedly, the journalist in Tripura was assaulted by a group of miscreants with sticks and sharp weapons while he was attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also stolen.

The journalist in Manipur was attacked while covering a flower festival in Laii Village of Senapathi District. He was shot twice with an air gun causing severe injuries.

In Kerala, the journalist was assaulted by a group of people when he reached Mangattukavala near Thoudupuzha. He was returning from a wedding function. Reportedly, in all three cases, the victims were hospitalised for treatment and cases were registered by the police.

NSK

(Release ID: 2181499) Visitor Counter : 228

Hans India

NHRC seeks report on attacks against journalists in Kerala, Manipur, Tripura

<https://www.thehansindia.com/news/national/nhrc-seeks-report-on-attacks-against-journalists-in-kerala-manipur-tripura-1016842>

IANS | 22 Oct 2025 6:04 PM IST

HIGHLIGHTS New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports about attacks on three journalists in separate...

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports about attacks on three journalists in separate incidents in Kerala, Manipur, and Tripura. The incidents reportedly occurred on August 30 in Kerala and Manipur, and on September 21 in Tripura. Taking serious note of the reports, the apex human rights body has issued notices to the Directors General of Police of the three states, seeking detailed reports on the matters within two weeks.

According to the press reports, in Tripura, a journalist was assaulted by a group of miscreants armed with sticks and sharp weapons while attending a clothes distribution programme organised by a political party in the Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also stolen. In Manipur, a journalist covering a flower festival in Laii village of Senapati district was attacked and shot twice with an air gun, sustaining severe injuries. In Kerala, another journalist was assaulted by a group of people near Mangattukavala in Thodupuzha while returning from a wedding function. Reportedly, in all three cases, the victims were hospitalised for treatment and FIRs were registered by the police.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights. Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India. The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Northeast Today

NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Journalist Assault in Tripura's Hezamara Along With Manipur and Kerala

<https://northeasttoday.in/northeast/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-journalist-assault-in-tripuras-hezamara-along-with-manipur-and-kerala/>

22nd October 2025

Agartala, October 22, 2025: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a brutal attack on a journalist in Hezamara under West Tripura district, issuing a notice to the state's Director General of Police and demanding a detailed report within two weeks.

The incident took place on September 21, 2025, during a clothes distribution programme organized by the Bharatiya Janata Party (BJP) as part of 'Seva Parv' celebrations marking Prime Minister Narendra Modi's birthday and the upcoming Durga Puja festivities.

According to reports, the journalist Kamal Kanti Tripura was assaulted by a group of miscreants wielding sticks and sharp weapons while covering the event. His motorcycle was also stolen during the attack. BJP workers present at the scene alleged that the attackers stormed the venue, disrupted the programme, and injured multiple attendees.

Chief Minister Dr Manik Saha along with All India Secretary of Indian Journalists Union (IJU) Pranab Sarkar also met with the journalist at GBP hospital in Agartala city on September 24. Former Chief Minister and BJP MP Biplab Kumar Deb visited the injured journalist at GBP Hospital and condemned the violence. He assured that an FIR would be filed and arrests made, adding that he had discussed the matter with Tipra Motha supremo Pradyot Kishore Debbarma.

The NHRC's action comes amid rising concerns over press safety, as the Commission also took cognizance of similar attacks on journalists in Kerala and Manipur on August 30. In Manipur, a journalist was shot twice with an air gun while covering a flower festival in Laii Village, Senapati district. In Kerala, another journalist was assaulted near Mangattukavala, Thoudupuzha, while returning from a wedding.

All three victims were hospitalized and police cases have been registered in each state. The NHRC's intervention highlights the urgent need for safeguarding media personnel, especially in politically sensitive regions like Tripura.

NE Now

NHRC seeks report from Tripura DGP over attacks on journalists

<https://nenow.in/north-east-news/tripura/nhrc-seeks-report-from-tripura-dgp-over-attacks-on-journalists.html>

by NE NOW NEWS | October 22, 2025 6: 36 pm

Guwahati: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports highlighting attacks on journalists in Tripura on September 21.

Acting on these reports, the Commission issued notices to Tripura's Director General of Police, Anurag Dhankar, and directed him to submit a detailed report on the incidents within two weeks.

According to the reports, a group of armed miscreants allegedly assaulted a journalist in Hezamara, West Tripura, while he was covering a clothes distribution programme organized by a political party.

The attackers reportedly used sticks and sharp weapons and stole the journalist's motorcycle during the incident.

On the same day, violence reportedly broke out at the same event, leaving several injured. Among the injured were BJP ST Morcha Vice President Mangal Debbarma, local journalist Kamal Kanti Tripura, and three other BJP workers.

Witnesses alleged that Tipra Motha supporters launched the attack during the programme.

The NHRC's action reflects growing national concern over the safety and protection of media professionals in the state.

Daijiworld

NHRC seeks reports from three states over journalist attacks

<https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=1295834>

Wed, Oct 22 2025 07:11:46 PM

Daijiworld Media Network - New Delhi

New Delhi, Oct 23: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports involving violent attacks on journalists in Kerala, Manipur, and Tripura, issuing notices to the Directors General of Police in each state. The Commission has demanded detailed action reports within two weeks.

The incidents, which occurred on August 30 in Kerala and Manipur, and on September 21 in Tripura, involve journalists being assaulted while on assignment or in public spaces, raising serious concerns over press freedom and safety.

In Tripura's Hezamara area, a journalist attending a clothes distribution programme organised by a political party was attacked by a mob wielding sticks and sharp weapons. His motorcycle was stolen during the assault.

In Manipur, a journalist covering a flower festival in Laii village, Senapati district, was shot twice with an air gun, sustaining critical injuries.

In Kerala's Thodupuzha region, a journalist was physically assaulted by a group while returning from a wedding function near Mangattukavala.

In all three cases, FIRs were filed, and the victims were hospitalised for treatment.

The NHRC, established under the Protection of Human Rights Act, 1993, has the power to act on its own motion (suo motu) in cases of human rights violations, including those flagged through media reports. The Commission has described these incidents as a serious threat to the fundamental right to freedom of expression, which includes the right of journalists to report freely and safely.

An NHRC official stated that the Commission is treating these matters with urgency, considering the increasing risks faced by media professionals across the country.

India Today NE

NHRC takes suo motu cognizance of attacks on journalists in Tripura, issues notice to DGP

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports concerning attacks on journalists in Tripura on 21st September.

<https://www.indiatodayne.in/tripura/story/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-attacks-on-journalists-in-tripura-issues-notice-to-dgp-1293839-2025-10-22>

Press Trust of India | Oct 22, 2025, Updated Oct 22, 2025, 5:13 PM IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports concerning attacks on journalists in Tripura on 21st September.

The Commission has issued notices to the Director General of Police of Tripura, Anurag Dhankar, seeking detailed reports on the incidents within two weeks.

According to reports, a journalist in Tripura was assaulted by a group of miscreants wielding sticks and sharp weapons while covering a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara, West Tripura. The journalist's motorcycle was also stolen during the attack.

On the same day, four BJP workers, including BJP ST Morcha vice president Mangal Debbarma, and journalist Kamal Kanti Tripura of a local TV channel sustained injuries after supporters of Tipra Motha allegedly attacked the cloth distribution event.

The NHRC's intervention underscores growing concerns about the safety of journalists in the state.

The Hawk

NHRC seeks report on attacks against journalists in Kerala, Manipur, Tripura

NHRC Probes Attacks on Journalists Across Three Indian States

<https://www.thehawk.in/news/india/nhrc-seeks-report-on-attacks-against-journalists-in-kerala-manipur-tripura>

The Hawk - Oct 22, 2025, 06:06 PM

New Delhi, Oct 23 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports about attacks on three journalists in separate incidents in Kerala, Manipur, and Tripura.

The incidents reportedly occurred on August 30 in Kerala and Manipur, and on September 21 in Tripura.

Taking serious note of the reports, the apex human rights body has issued notices to the Directors General of Police of the three states, seeking detailed reports on the matters within two weeks.

According to the press reports, in Tripura, a journalist was assaulted by a group of miscreants armed with sticks and sharp weapons while attending a clothes distribution programme organised by a political party in the Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also stolen.

In Manipur, a journalist covering a flower festival in Laii village of Senapati district was attacked and shot twice with an air gun, sustaining severe injuries.

In Kerala, another journalist was assaulted by a group of people near Mangattukavala in Thodupuzha while returning from a wedding function.

Reportedly, in all three cases, the victims were hospitalised for treatment and FIRs were registered by the police.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights. Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India. The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

--IANS^[1]_{SEP}

pds/vd

Orissa Diary

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported attacks on three journalists in Kerala, Manipur and Tripura

<https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-attacks-on-three-journalists-in-kerala-manipur-and-tripura/>

By: Odisha Diary Bureau | Date: October 22, 2025

The National Human Rights Commission, (NHRC) India, has taken suo motu cognizance of media reports about the attack on three journalists at different places in Kerala and Manipur on 30th August, 2025 and Tripura on 21st September, 2025. In all three cases, the Commission has issued notices to the Director Generals of Police of the three states, calling for detailed reports on the matters within two weeks.

Reportedly, the journalist in Tripura was assaulted by a group of miscreants with sticks and sharp weapons while he was attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also stolen.

The journalist in Manipur was attacked while covering a flower festival in Laii Village of Senapathi District. He was shot twice with an air gun causing severe injuries.

In Kerala, the journalist was assaulted by a group of people when he reached Mangattukavala near Thoudupuzha. He was returning from a wedding function. Reportedly, in all three cases, the victims were hospitalised for treatment and cases were registered by the police.

ANI News

NHRC takes suo motu cognisance of attacks on journalists in Kerala, Manipur, Tripura

<https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-attacks-on-journalists-in-kerala-manipur-tripura20251022164535/>

ANI | Updated: Oct 22, 2025 16:45 IST

New Delhi [India], October 22 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognizance of media reports highlighting three separate incidents of alleged assault on journalists in Kerala, Manipur, and Tripura. In response, the Commission has issued notices to the Directors General of Police (DGPs) of the respective states, demanding detailed reports on each case within a two-week timeframe.

The reported attacks occurred on August 30, 2025, in Kerala and Manipur, and on September 21, 2025, in Tripura. In all three cases, the journalists were allegedly assaulted either while carrying out their professional responsibilities or while returning from work-related engagements.

In Tripura, a journalist was reportedly attacked by a group of miscreants wielding sticks and sharp weapons during a clothes distribution programme organised by a political party in the Hezamara area of West Tripura. The assailants also stole his motorcycle during the incident. In Manipur, another journalist sustained serious injuries after being shot twice with an air gun while covering a flower festival at Laii Village in Senapati District. Meanwhile, in Kerala, a journalist was allegedly beaten by a group of individuals near Mangattukavala in Thodupuzha as he was returning from a wedding function. All three victims required hospitalisation, and criminal cases were registered by the local police. Recognising the seriousness of these assaults, the NHRC has instructed the DGPs of Kerala, Manipur, and Tripura to submit comprehensive reports detailing the circumstances and actions taken.

The Commission emphasised the importance of ensuring that journalists can operate without fear or obstruction, as their role is vital to upholding democratic values and promoting transparency.

The NHRC frequently initiates action based on media reports or complaints that indicate potential human rights violations, particularly those affecting press freedom and journalist safety. In recent years, the Commission has increasingly advocated for robust protection measures for media personnel, especially in regions marked by political sensitivity or conflict, stated a press statement issued by NHRC.

(ANI)

News on Air

NHRC Seeks Reports from Kerala, Manipur, Tripura Over Attacks on Journalists

<https://www.newsonair.gov.in/nhrc-seeks-reports-from-kerala-manipur-tripura-over-attacks-on-journalists/>

Site Admin | October 22, 2025 4:56 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) India has issued a notice to the Chief Secretary of Kerala, Manipur and Tripura in the matter of reported attacks on journalists at different places, calling for detailed reports on the matters within two weeks. Reportedly, in all three cases, the victims were hospitalised for treatment and cases were registered by the police.

Taking suo motu cognizance of media reports, the Commission has asked the DGP of the following state to intimate the present status of investigation in the case and the steps taken to ensure that such incidents do not recur in future.

Mathrubhumi

Journalist assaults trigger NHRC probe; three states asked to submit reports

<https://english.mathrubhumi.com/news/india/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-assaults-journalists-kerala-manipur-tripura-l83zr0r1>

News Desk

22 October 2025, 07:36 PM IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognisance of three separate attacks on journalists in Kerala, Manipur, and Tripura

New Delhi: The NHRC of India has acted following media reports of assaults on journalists at different locations in Kerala, Manipur, and Tripura.

The incidents occurred on August 30, 2025, in Kerala and Manipur, and on September 21, 2025, in Tripura. In response, the Commission has instructed the Directors General of Police (DGPs) of the three states to submit detailed reports on the incidents within a fortnight.

In Tripura, a journalist covering a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara, West Tripura, was attacked by a group wielding sticks and sharp weapons. His motorcycle was also stolen. In Manipur, a journalist sustained severe injuries after being shot twice with an air gun while covering a flower festival in Laii Village, Senapati District. Meanwhile, in Kerala, a journalist was reportedly assaulted near Mangattukavala, Thodupuzha, as he returned from a wedding function. All three victims were hospitalised, and police registered cases in each instance.

The NHRC emphasised that journalists must be able to operate without fear or obstruction, given their critical role in upholding democracy and transparency. The Commission's notices demand comprehensive details about the incidents, the measures taken, and steps planned to prevent recurrence.

NHRC action highlights the growing concern over media personnel safety in India, particularly in politically sensitive regions. The Commission has frequently acted on complaints and media reports indicating human rights violations, underscoring the need for strong protection measures for journalists.

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognisance of assaults on three journalists in Kerala, Manipur, and Tripura, following media reports. The assaults occurred on August 30, 2025, in Kerala and Manipur, and on September 21, 2025, in Tripura. In each case, journalists were allegedly attacked while carrying out professional duties or returning from work-related engagements.

In Tripura, the victim, attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara, West Tripura, was assaulted by a group of miscreants with sticks and sharp weapons. During the attack, his motorcycle was also stolen. In Manipur, a journalist

was shot twice with an air gun while covering a flower festival in Laii Village, Senapati District, resulting in severe injuries. In Kerala, a journalist returning from a wedding function in Mangattukavala, Thodupuzha, was beaten by a group of individuals. All three victims required hospitalisation, and police have registered cases in each state.

The NHRC has issued notices to the DGPs of Kerala, Manipur, and Tripura, directing them to submit detailed reports within two weeks, including the circumstances of the assaults and the measures taken. The Commission emphasised that journalists play a vital role in maintaining democratic values and ensuring transparency, and their safety must be guaranteed.

Historically, the NHRC has acted on media reports or complaints indicating potential human rights violations, especially those affecting press freedom. With increasing attacks on journalists in sensitive regions, the Commission continues to advocate for strong protection measures, reinforcing the importance of a safe working environment for media personnel.

(With ANI inputs)

Financial Express

NHRC takes suo motu cognisance of journalists' assault, sends notice to police chiefs of three states

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the DGPs of Kerala, Manipur, and Tripura after taking suo motu cognizance of three separate attacks on journalists in August and September.

<https://www.financialexpress.com/india-news/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-journalists-assault-sends-notice-to-police-chiefs-of-three-states/4018581/>

Written by Aniket Sharma

October 22, 2025 23:18 IST

NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Attacks on Three Journalists in Kerala, Manipur, and Tripura.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday said that it has issued notices to police chiefs of Kerala, Manipur and Tripura over reports of an alleged attack on three journalists in separate incidents. In all three cases, the victims were reportedly hospitalised for treatment and cases were registered by the police.

The NHRC has asked for a detailed report on the three cases. The commission has “taken suo motu cognisance of media reports about the attack on three journalists at different places, in Kerala and Manipur on August 30, and in Tripura on September 21,” the statement said.

A look at assault cases on Journo's

A journalist attending a political party's clothes distribution event in the Hezamara area of West Tripura was allegedly attacked by a group using sticks and sharp weapons. His motorcycle was also reportedly stolen during the assault.

While covering a flower festival in Senapathi District's Laii Village, a journalist was attacked and shot twice with an air gun, resulting in severe injuries.

A journalist was allegedly assaulted by a group of people when he reached Mangattukavala near Thoudupuzha, as he was returning home from a wedding function.

Hindu

NHRC issues notice to three States over attack on journalists

The National Human Rights Commission asked the Director Generals of Police of Kerala, Tripura and Manipur for detailed reports on the matter within two weeks

Updated - October 22, 2025 09:14 pm IST - New Delhi

The Hindu Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday (October 22, 2025) issued a notice to the Kerala, Tripura and Manipur governments over the alleged attack on three journalists at different places in the States in the past three months.

The commission has asked the Director Generals of Police of the three States, calling for detailed reports on the matters within two weeks.

According to a communique from the commission, a journalist in Manipur was attacked on August 30 while covering a flower festival in Laii Village of Senapati District. He was shot twice with an air gun and was severely injured.

The same day, another journalist was assaulted by a group of people when he reached Mangattukavala near Thoudupuzha, Kerala. He was returning from a wedding function.

In another case in Tripura, a journalist was assaulted with sticks and sharp weapons by a group of miscreants on September 21. He was attending a clothes distribution programme organised by a political party in the Hezamara area of west Tripura. His motorcycle was also stolen.

In all three incidents, the victims were hospitalised for treatment and cases were registered by the police.

Tripura News

NHRC seeks reports from Tripura, Manipur and Kerala over attacks on scribes

<https://tripuratimes.com/times/nhrc-seeks-reports-from-tripura-manipur-and-kerala-over-attacks-on-scribes-32387.html>

Oct 22, 2025 Agartala, TRIPURATIMES Desk117

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports on attacks on three journalists in separate incidents in Tripura, Manipur and Kerala and sought action taken reports from the police chiefs of the three states.

The incidents occurred in Tripura on 21 September 2025 and in Manipur and Kerala on 30 August 2025. The Commission has issued notices to the Directors General of Police of the three states, asking them to submit detailed reports within two weeks.

According to reports, a journalist in Tripura was assaulted by a group of miscreants armed with sticks and sharp weapons while he was covering a clothes distribution programme organised by a political party in the Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also allegedly stolen during the attack.

In Manipur, another journalist was targeted while covering a flower festival at Laii village in Senapati district. He was shot twice with an air gun and sustained serious injuries.

In Kerala, a journalist was reportedly attacked by a group of people at Mangattukavala near Thodupuzha on his way back from a wedding function.

All three victims were admitted to hospital for treatment and police have registered cases in connection with the incidents, reports said.

The Commission observed that attacks on journalists while they are discharging their professional duties raise serious concerns about the safety of media persons and the freedom of the press. It said the state authorities are duty-bound to ensure a safe environment for journalists to work without fear or intimidation. (WITH INPUTS FROM PIB)

PTI

NHRC issues notices to DGPs of three states over attack on journalists

<https://www.ptinews.com/editor-detail/nhrc-issues-notices-to-dgps-of-three-states-over-attack-on-journalists/3028075>

NEW DELHI: (Oct 22) The National Human Rights Commission on Wednesday said it has issued notices to police chiefs of Kerala, Manipur and Tripura over reports of alleged attack on three journalists in the past two months.

In a statement, the NHRC said it has sought detailed reports on the three cases in two weeks.

The Commission has "taken suo motu cognisance of media reports about the attack on three journalists at different places, in Kerala and Manipur on August 30, and in Tripura on September 21," it said.

Northeast Herald

NHRC, India takes suo motu cognizance against attacks on 3 journalists in Kerala, Manipur and Tripura

Issues notices to the Director Generals of Police of the three states, calling for detailed reports on the matters within two weeks

<https://neherald.com/tripura/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-against-attacks-on-3-journalists-in-kerala-manipur-and-tripura>

NEH Report | Oct 22, 2025

5 min read

The National Human Rights Commission, (NHRC) India, has taken suo motu cognizance of media reports about the attack on three journalists at different places in Kerala and Manipur on 30th August, 2025 and Tripura on 21st September, 2025. In all three cases, the Commission has issued notices to the Director Generals of Police of the three states, calling for detailed reports on the matters within two weeks.

Reportedly, the journalist in Tripura was assaulted by a group of miscreants with sticks and sharp weapons while he was attending a clothes distribution programme organised by a political party in Hezamara area of West Tripura. His motorcycle was also stolen.

The journalist in Manipur was attacked while covering a flower festival in Laii Village of Senapathi District. He was shot twice with an air gun causing severe injuries.

In Kerala, the journalist was assaulted by a group of people when he reached Mangattukavala near Thoudupuzha. He was returning from a wedding function. Reportedly, in all three cases, the victims were hospitalized for treatment and cases were registered by the police.

NewsroomPost

NHRC takes suo motu cognisance of attacks on journalists in Kerala, Manipur, Tripura

The assailants also stole his motorcycle during the incident. In Manipur, another journalist sustained serious injuries after being shot twice with an air gun while covering a flower festival at Laii Village in Senapati District.

<https://newsroompost.com/india/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-attacks-on-journalists-in-kerala-manipur-tripura/5349738.html/amp>

ANI

15 hours ago

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognisance of media reports highlighting three separate incidents of alleged assault on journalists in Kerala, Manipur, and Tripura.

In response, the Commission has issued notices to the Directors General of Police (DGPs) of the respective states, demanding detailed reports on each case within a two-week timeframe.

The reported attacks occurred on August 30, 2025, in Kerala and Manipur, and on September 21, 2025, in Tripura. In all three cases, the journalists were allegedly assaulted either while carrying out their professional responsibilities or while returning from work-related engagements.

In Tripura, a journalist was reportedly attacked by a group of miscreants wielding sticks and sharp weapons during a clothes distribution program organized by a political party in the Hezamara area of West Tripura.

The assailants also stole his motorcycle during the incident. In Manipur, another journalist sustained serious injuries after being shot twice with an air gun while covering a flower festival at Laii Village in Senapati District.

Meanwhile, in Kerala, a journalist was allegedly beaten by a group of individuals near Mangattukavala in Thodupuzha as he was returning from a wedding function. All three victims required hospitalization, and criminal cases were registered by the local police.

Recognizing the seriousness of these assaults, the NHRC has instructed the DGPs of Kerala, Manipur, and Tripura to submit comprehensive reports detailing the circumstances and actions taken.

The Commission emphasized the importance of ensuring that journalists can operate without fear or obstruction, as their role is vital to upholding democratic values and promoting transparency.

The NHRC frequently initiates action based on media reports or complaints that indicate potential human rights violations, particularly those affecting press freedom and journalist safety. In recent years, the Commission has increasingly advocated for robust protection measures for media personnel, especially in regions marked by political sensitivity or conflict, stated a press statement issued by NHRC.

Devdiscourse

NHRC Investigates Attacks on Journalists in Three Indian States

The NHRC has issued notices to police chiefs of Kerala, Manipur, and Tripura about alleged attacks on journalists. The attacks occurred in August and September, resulting in hospitalizations and police investigations. The NHRC seeks detailed reports on these incidents within two weeks.

<https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3671296-gaza-ceasefire-a-fragile-peace-and-the-path-ahead>

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 22-10-2025 20:56 IST | Created: 22-10-2025 20:56 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has demanded accountability from the police departments of Kerala, Manipur, and Tripura following reports of attacks on journalists in recent months.

According to the NHRC, three separate incidents occurred: one in Kerala, one in Manipur, and another in Tripura. These attacks have prompted the Commission to seek explanations and detailed reports from the police within two weeks.

In the most recent case in Tripura, a journalist was reportedly assaulted by a group using sticks and sharp weapons during a political event, also resulting in the theft of his motorcycle. A journalist in Manipur sustained serious injuries after being shot twice with an air gun while covering a flower festival, and a journalist in Kerala was attacked while attending a personal event. Each incident has led to police cases and hospitalizations, emphasizing the pressing nature of these attacks on media personnel.

(With inputs from agencies.)

LatestLY

India News | NHRC Takes Suo Motu Cognisance of Attacks on Journalists in Kerala, Manipur, Tripura

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognizance of media reports highlighting three separate incidents of alleged assault on journalists in Kerala, Manipur, and Tripura.

<https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-attacks-on-journalists-in-kerala-manipur-tripura-7171447.html/amp>

ANI Oct 22, 2025 04:58 PM IST

New Delhi [India], October 22 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognizance of media reports highlighting three separate incidents of alleged assault on journalists in Kerala, Manipur, and Tripura.

In response, the Commission has issued notices to the Directors General of Police (DGPs) of the respective states, demanding detailed reports on each case within a two-week timeframe.

The reported attacks occurred on August 30, 2025, in Kerala and Manipur, and on September 21, 2025, in Tripura. In all three cases, the journalists were allegedly assaulted either while carrying out their professional responsibilities or while returning from work-related engagements.

In Tripura, a journalist was reportedly attacked by a group of miscreants wielding sticks and sharp weapons during a clothes distribution programme organised by a political party in the Hezamara area of West Tripura.

The assailants also stole his motorcycle during the incident. In Manipur, another journalist sustained serious injuries after being shot twice with an air gun while covering a flower festival at Laii Village in Senapati District.

Meanwhile, in Kerala, a journalist was allegedly beaten by a group of individuals near Mangattukavala in Thodupuzha as he was returning from a wedding function. All three victims required hospitalisation, and criminal cases were registered by the local police.

Recognising the seriousness of these assaults, the NHRC has instructed the DGPs of Kerala, Manipur, and Tripura to submit comprehensive reports detailing the circumstances and actions taken.

The Commission emphasised the importance of ensuring that journalists can operate without fear or obstruction, as their role is vital to upholding democratic values and promoting transparency.

The NHRC frequently initiates action based on media reports or complaints that indicate potential human rights violations, particularly those affecting press freedom and journalist safety. In recent years, the Commission has increasingly advocated for robust protection measures for media personnel, especially in regions marked by political sensitivity or conflict, stated a press statement issued by NHRC. (ANI)

(The above story is verified and authored by ANI staff, ANI is South Asia's leading multimedia news agency with over 100 bureaus in India, South Asia and across the globe. ANI brings the latest news on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Health, Fitness, Entertainment, & News. The views appearing in the above post do not reflect the opinions of LatestLY)

The Print

पत्रकारों पर हमले को लेकर एनएचआरसी ने तीन राज्यों के डीजीपी को नोटिस जारी किया

<https://hindi.theprint.in/india/nhrc-issues-notices-to-dgps-of-three-states-over-attacks-on-journalists/884746/>

भाषा | 22 October, 2025

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को कहा कि उसने पिछले दो महीनों में तीन पत्रकारों पर कथित हमले की खबरों को लेकर केरल, मणिपुर और त्रिपुरा के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने तीन मामलों पर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा, “30 अगस्त को केरल और मणिपुर में तथा 21 सितंबर को त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तीन पत्रकारों पर हमले के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है।”

तीनों मामलों में एनएचआरसी ने पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

त्रिपुरा में पत्रकार पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया था। हमला तब किया गया जब वह पश्चिमी त्रिपुरा के हेज़ामारा इलाके में एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसमें कहा गया है कि उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई।

मणिपुर के सेनापति जिले के लाई गांव में एक पुष्प उत्सव की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार पर कथित तौर पर हमला किया गया। बयान में कहा गया है कि उन्हें एयर गन से दो बार गोली मारी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

केरल में एक पत्रकार पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने उस समय हमला किया जब वह थौदुपुझा के पास मंगट्टुकवाला में एक शादी समारोह से लौट रहे थे।

तीनों मामलों में पीड़ितों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है। इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है।

Amar Ujala

NHRC: पत्रकारों पर हमले के मामलों का राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, तीन राज्य के DGP को भेजा नोटिस

<https://www.amarujala.com/india-news/national-human-rights-commission-issues-notice-to-dgp-of-kerala-manipur-and-tripura-over-journalist-attacks-2025-10-22?pagelid=1>

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Wed, 22 Oct 2025 10:03 PM IST

सार

देश

एनएचआरसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अलग-अलग राज्यों में तीन पत्रकारों पर हुए हमलों का संज्ञान लिया है। ये घटनाएं 30 अगस्त को केरल और मणिपुर में हुई थीं। इसके अलावा एक घटना 21 सितंबर को त्रिपुरा में हुई थी।

विस्तार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पत्रकारों पर हमले की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केरल, मणिपुर और त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने तीनों मामलों पर दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अलग-अलग राज्यों में तीन पत्रकारों पर हुए हमलों का संज्ञान लिया है। ये घटनाएं 30 अगस्त को केरल और मणिपुर में हुई थीं। इसके अलावा एक घटना 21 सितंबर को त्रिपुरा में हुई थी। आयोग ने कहा कि सभी मामलों में संबंधित राज्यों के डीजीपी को नोटिस जारी कर विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है।

क्या थी पत्रकारों पर हमले की घटनाएं?

त्रिपुरा की घटना में एक पत्रकार पर पश्चिम त्रिपुरा के हेजमारा क्षेत्र में एक राजनीतिक दल की तरफ से आयोजित कपड़ा वितरण कार्यक्रम के दौरान लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया गया था। हमलावरों ने उसका मोटरसाइकिल भी चुरा लिया था।

मणिपुर में एक पत्रकार पर सेनापति जिले के लाई गांव में आयोजित फूल महोत्सव की रिपोर्टिंग के दौरान एयर गन से दो बार गोली चलाई गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

केरल की घटना में एक पत्रकार पर थोडुपुझा के पास मंगट्टुकवाला क्षेत्र में शादी समारोह से लौटते समय लोगों के एक समूह ने हमला किया था। तीनों ही मामलों में पीड़ित पत्रकारों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

Janta Se Rishta

NHRC ने केरल, मणिपुर, त्रिपुरा में पत्रकारों पर हमलों पर रिपोर्ट मांगी

<https://jantaserishta.com/local/kerala/nhrc-seeks-report-on-attacks-on-journalists-in-kerala-manipur-tripura-4337867>

Dolly 22 Oct 2025 6:11 PM

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केरल, मणिपुर और त्रिपुरा में अलग-अलग घटनाओं में तीन पत्रकारों पर हुए हमलों की मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है।

ये घटनाएँ कथित तौर पर केरल और मणिपुर में 30 अगस्त को और त्रिपुरा में 21 सितंबर को हुईं। रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए, शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, त्रिपुरा में, पश्चिमी त्रिपुरा के हेज़ामारा क्षेत्र में एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित वस्त्र वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान लाठी और धारदार हथियारों से लैस बदमाशों के एक समूह ने एक पत्रकार पर हमला किया। उसकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। मणिपुर में, सेनापति जिले के लाई गाँव में एक पुष्प उत्सव को कवर कर रहे एक पत्रकार पर हमला किया गया और एयर गन से दो गोली मारी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। केरल में, एक अन्य पत्रकार पर थोडुपुझा के मंगट्टुक्वाला के पास एक शादी समारोह से लौटते समय लोगों के एक समूह ने हमला किया। कथित तौर पर, तीनों मामलों में पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो मानवाधिकारों के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक है। इसकी प्राथमिक भूमिका मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है, जिन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। शीर्ष मानवाधिकार निकाय के पास मानवाधिकार उल्लंघन की औपचारिक शिकायत प्राप्त किए बिना, मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक जानकारी या अन्य स्रोतों के आधार पर स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का अधिकार है।

News on Air

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किया नोटिस

<https://www.newsonair.gov.in/hi/>

Site Admin | अक्टूबर 22, 2025 5:48 अपराह्न

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न स्थानों पर पत्रकारों पर हमलों को देखते हुए केरल, मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

इन राज्यों में तीन मामलों में पीड़ितों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मामले दर्ज कर लिये हैं। मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने इन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से जांच की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने के कदम उठाने को भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।

NHRC.NIC

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported finding of the dead body of a differently-abled RTI activist after being abducted in Tharad district, Gujarat

Press Release

National Human Rights Commission

<https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-finding-of-the-dead-body-of-a-differently-abled-rti-activist-after-being-abducted-in-tharad-district,-gujarat>

New Delhi: 22nd October, 2025

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported finding of the dead body of a differently-abled RTI activist after being abducted in Tharad district, Gujarat

Issues a notice to the State DGP, calling for a detailed report on the matter within two weeks

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a differently-abled RTI activist was found dead in a canal after being abducted by unidentified persons from an area near his residence in the Tharad district, Gujarat on 12th October, 2025. Reportedly, the victim's body was found in a canal on 14th October, 2025.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Director General of Police, Gujarat, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 15th October, 2025, the victim had filed complaints with the authorities regarding alleged forged beneficiary documents and other irregularities by the local builders in the slum redevelopment project under the Public-Private Partnership scheme.

Times Now

NHRC Takes Note of RTI Activist's Death After Abduction in Gujarat

<https://www.timesnownews.com/india/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-finding-of-the-dead-body-of-a-differently-abled-rti-activist-after-being-abducted-in-tharad-district-gujarat-article-153037161>

Written by: Shivam Sharma

Updated Oct 22, 2025, 21:55 IST

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim.

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a differently-abled RTI activist was found dead in a canal after being abducted by unidentified persons from an area near his residence in the Tharad district, Gujarat on 12th October, 2025. Reportedly, the victim's body was found in a canal on 14th October, 2025.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Director General of Police, Gujarat, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 15th October, 2025, the victim had filed complaints with the authorities regarding alleged forged beneficiary documents and other irregularities by the local builders in the slum redevelopment project under the Public-Private Partnership scheme.

The News Minute

Telangana SHRC takes suo moto cognisance of encounter killing by police

Telangana State Human Rights Commission (SHRC) has taken suo moto cognisance of the killing of an accused in the murder of a policeman in an alleged encounter by the police at a hospital in Nizamabad town and directed the Director General of Police to submit a report.

<https://www.thenewsminute.com/amp/story/telangana/telangana-shrc-takes-suo-moto-cognisance-of-encounter-killing-by-police>

Written by : IANS

Published:22nd Oct, 2025 at 5:53 PM

Telangana State Human Rights Commission (SHRC) has taken suo moto cognisance of the killing of an accused in the murder of a policeman in an alleged encounter by the police at a hospital in Nizamabad town and directed the Director General of Police to submit a report.

The Human Rights Commission on Tuesday took note of newspaper reports about Monday's incident in Nizamabad, in which an accused in the murder of a police Constable was shot dead by the police in an alleged encounter.

Sheikh Riyaz, who was recently arrested in connection with the murder of police Constable Pramod Kumar, died in the encounter at the hospital where he was undergoing treatment.

It is reported that the said accused attempted to snatch the service weapon of an Armed Reserve Constable and tried to escape, following which the police opened fire, claiming self-defence, leading to his instantaneous death.

As per the statement of B. Shivadhar Reddy, Director General of Police, Telangana, the incident occurred in self-defence as the accused allegedly tried to fire at the police personnel, noted the Commission.

"The incident, as reported, involves custodial circumstances, and raises important questions relating to the Right to Life under Article 21 of the Constitution of India, as well as compliance with the guidelines issued by the Hon'ble Supreme Court in People's Union for Civil Liberties vs State of Maharashtra (2014) 10 SCC 635 and NHRC Guidelines (2010, reaffirmed 2014) concerning encounter deaths. In view of the gravity and human rights implications of the matter, the Commission is of the considered opinion that it is a fit case for suo-motu cognisance under Regulation 25 of the A.P. State Human Rights Commission (Procedure) Regulations, 2013," the Commission said.

While taking suo-motu cognisance of the alleged encounter death of Riyaz, the Commissioner directed the DGP to submit a detailed factual report on the next hearing on October 24 about circumstances leading to the encounter, status of magisterial enquiry

and any departmental/judicial proceedings ordered, and also compliance with the NHRC and Supreme Court guidelines on encounter deaths, along with a copy of the FIR and post-mortem report.

Riyaz had allegedly stabbed police Constable Pramod Kumar (42) to death while he was escorting him to a police station in Nizamabad on October 17.

The DGP had ordered a manhunt for the accused, who had escaped after killing the Constable.

Riyaz attacked a man named Asif near Sarangapur under Nizamabad Town 6 Police Station limits on October 19. Asif, who was helping the police in apprehending him, suffered serious injuries during the scuffle. Both men were shifted to hospital for treatment, and Riyaz was later taken into custody.

According to police, Riyaz was involved in 61 cases including three attempts to murder, robbery and snatching. There were 50 theft cases against him including six in Maharashtra.

The Indian Express

Telangana human rights body flags Nizamabad hospital encounter, seeks 'detailed factual report' from DGP

<https://indianexpress.com/article/cities/hyderabad/telegana-human-rights-body-flags-nizamabad-hospital-encounter-seeks-detailed-factual-report-from-dgp-10320178/>

October 22, 2025

The Telangana Human Rights Commission (TGHRC) on Tuesday took suo motu cognisance of an alleged encounter at Nizamabad Government General Hospital that led to the death of a vehicle theft offender, and directed Director General of Police (DGP) B Shivadhar Reddy "to submit a detailed factual report covering the circumstances leading to the incident".

The incident took place on Monday when Shaik Riyaz was killed in an exchange of fire at the hospital when he tried to snatch a weapon from a police constable in his bid to escape, as per the police.

"The incident, as reported, involves custodial circumstances, and raises important questions relating to the right to life under Article 21 of the Constitution of India, as well as compliance with the guidelines issued by the Hon'ble Supreme Court in People's Union for Civil Liberties v. State of Maharashtra (2014) 10 SCC 635 and NHRC Guidelines (2010, reaffirmed 2014) concerning encounter deaths," the commission stated.

It further directed DGP Reddy "to submit a detailed factual report covering the circumstances leading to the incident, the status of any magisterial or judicial inquiry, and compliance with the Supreme Court and NHRC guidelines on encounter deaths, along with copies of the FIR and post-mortem report". The report must reach the commission by November 24, it added.

According to police, Riyaz was an accused in the murder of Police Constable M Pramod Kumar, 42. On Monday, Riyaz allegedly attempted to escape after attacking police officers at the Nizamabad government hospital. "The police made strenuous efforts to apprehend Riyaz. He tried to snatch a weapon from the police and fire at the officers. In the attempt by the police to subdue Riyaz, he was killed," a release from DGP Reddy had stated. "Today, he attempted to snatch a firearm from the police and fire at the officers while attempting to escape. In the ensuing shootout, Riyaz was killed," the release added.

Further, the DGP stated that the government and police department would support Kumar's wife, Praneetha, and their three sons. "We will support Pramod's family by granting an ex-gratia of Rs 1 crore as per GO Rt No. 411, last paid salary till the retirement of the martyred constable, a government job for one of the family members, a 300-yard house as per GO155, as well as an ex-gratia of Rs 16 lakh from police security and Rs 8 lakh from police welfare," the DGP stated.

Kumar was allegedly stabbed to death by Riyaz when he was escorting the latter to the police station on Friday night in connection with a bike theft case. Kumar was rushed to the Nizamabad Government General Hospital, but doctors pronounced him brought dead.

Kashmir Media Services

Telangana rights body seeks report over custodial killing of Muslim youth

<https://kmsnews.org/kms/2025/10/22/telangana-rights-body-seeks-report-over-custodial-killing-of-muslim-youth.html>

October 22, 2025Last Updated: October 22, 2025

Hyderabad: The Telangana State Human Rights Commission (SHRC) has taken suo motu cognisance of the custodial killing of a Muslim youth, Sheikh Riyaz, at a hospital in Nizamabad town, directing the state's Director General of Police to submit a detailed report on the incident.

According to Kashmir Media Service, Riyaz, who was recently arrested in connection with the murder of police Constable Pramod Kumar, was shot dead by police inside the hospital where he was receiving treatment. Police claimed the youth tried to snatch a constable's service weapon and attempted to escape.

The Commission, however, noted that the incident occurred under custodial circumstances, raising serious concerns about the violation of the Right to Life under Article 21 of the Indian Constitution and non-compliance with Supreme Court and National Human Rights Commission (NHRC) guidelines on encounter deaths.

"The matter has grave human rights implications and warrants independent scrutiny," the SHRC stated, citing its authority under Regulation 25 of the A.P. State Human Rights Commission (Procedure) Regulations, 2013. It directed the DGP to furnish a factual report by October 24, detailing the circumstances of the encounter, the status of the magisterial inquiry, copies of the FIR and post-mortem report, and compliance with the NHRC and Supreme Court guidelines.

Deccan Chronicle

Riyaz Shot Dead, HRC Takes Cognizance

<https://www.deccanchronicle.com/southern-states/teelangana/riyaz-shot-dead-hrc-takes-cognizance-1911665>

Narender Pulloor | 22 October 2025

Nizamabad: Sheik Riyaz, accused of murdering police constable E. Pramod Kumar during his arrest last week, was killed in a police encounter in Nizamabad on Monday. Riyaz was injured in an altercation with a man, Asif, on Sunday while trying to escape. He was then arrested by the police and taken to the Government General Hospital for treatment.

While undergoing treatment at the hospital, Riyaz allegedly tried to escape by attacking a police constable posted on guard duty with his service weapon. To protect the constable and medical staff, an armed reserve sub-inspector opened fire and killed Riyaz.

Nizamabad commissioner P. Sai Chaitanya said Riyaz said loud sounds were heard from Riyaz's ward on Monday. The armed reserve constable and sub-inspector rushed to the scene and tried to pacify the accused. Riyaz, however, snatched the weapon from the constable and attempted to fire.

The sub-inspector immediately opened fire to save the constable and hospital staff. Riyaz died on the spot. A case has been registered and further details will emerge from the investigation, the commissioner said.

The body of Riyaz was handed over to his family members, who performed the last rites on Tuesday.

Meanwhile, the Telangana Human Rights Commission (TGHRC) took suo motu cognizance of the encounter and directed DGP B. Shivdhar Reddy to submit a detailed factual report outlining the circumstances leading to Riyaz's death. The commission also asked the DGP to furnish details of any magisterial or judicial inquiry and compliance with Supreme Court and NHRC guidelines on encounter deaths, along with copies of the FIR and post-mortem report, by November 24.

The commission observed that the incident, involving custodial circumstances, raised serious concerns regarding the right to life under Article 21 of the Constitution and compliance with Supreme Court and NHRC guidelines on encounter deaths. Given the gravity and human rights implications, the commission stated it was a fit case for suo motu cognizance under Regulation 25 of the A.P. State Human Rights Commission (Procedure) Regulations, 2013.

DGP Shivadhar Reddy, IG S. Chandrasekhar Reddy and Sai Chaitanya visited the residence of slain constable Pramod Kumar and consoled the bereaved family. The DGP said Chief Minister A. Revanth Reddy had announced Rs 1 crore ex gratia for the family.

Navbharat Times

निजामाबाद में वाहन चोर को पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली मारी, दो पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला

<https://navbharattimes.indiatimes.com/epaper/2025/oct/october22/nizamabad-police-shoots-vehicle-thief-in-self-defense-case-of-two-policemens-murder/articleshow/124728796.cms>

TOI.in•22 Oct 2025, 12:51 pm

निजामाबाद में एक खूंखार वाहन चोर को पुलिस ने मार गिराया। यह चोर दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने एक पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने उसे गोली मार दी। इस अपराधी पर कई गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस ने कानून के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी की हैं।

हैदराबाद: एक 28 वर्षीय वाहन चोर, जिसने निजामाबाद में एक पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, सोमवार को एक सरकारी अस्पताल में एक इंस्पेक्टर की गोली से मारा गया। पुलिस का कहना है कि उसने एक कांस्टेबल से राइफल छीनने की कोशिश की थी। मृतक की पहचान एसके रियाज के तौर पर हुई है। रियाज को गिरफ्तारी के दौरान लगी चोटों का इलाज चल रहा था। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने बताया कि नियमित जांच के लिए ड्यूटी पर मौजूद पुलिस टीम ने रियाज के कमरे से तेज आवाजें सुनीं और पूछताछ के लिए वहां पहुंची। जैसे ही वे कमरे में घुसे, रियाज ने अचानक कांस्टेबल से राइफल छीनने की कोशिश की और ट्रिगर दबाने का प्रयास किया। चेतावनी के बावजूद, रियाज हिंसक बना रहा, जिससे रिजर्व इंस्पेक्टर के पास उसे गोली मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा।

वन टाउन पुलिस को दिए अपने बयान में, निजामाबाद सिटी आर्म्ड रिजर्व (CAR) के इंस्पेक्टर एच सतीश, जिन्होंने रियाज को गोली मारी थी, ने बताया कि वे 20 अक्टूबर को निजामाबाद सरकारी जनरल अस्पताल में नियमित ड्यूटी के तहत कैदी सुरक्षा जांच के लिए तैनात थे। सुबह 11:30 बजे, जब वे अस्पताल पहुंचे, तो उन्होंने अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 407 से तेज शोर और चिल्लाने की आवाजें सुनीं।

इंस्पेक्टर सतीश ने अपने बयान में कहा, "आरोपी रियाज दरवाजों पर धक्का मार रहा था और रोशनदानों के शीशे तोड़ रहा था। मैंने एक कांस्टेबल को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया। एक एसआई और एक कांस्टेबल के साथ, मैं कमरे में दाखिल हुआ। हमने उसे काबू किया और उसे खाट पर बिठाया। रियाज ने विरोध किया और जब कांस्टेबल मुड़ा, तो उसने अचानक कांस्टेबल की एसएलआर छीन ली और फायर करने की कोशिश की। चूंकि हथियार में गोली थी, मैंने रियाज को उसे छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका। आत्मरक्षा में और एक त्रासदी को रोकने के लिए, मैंने रियाज पर गोली चला दी।"

रियाज को सीने में छह गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इंस्पेक्टर सतीश की शिकायत पर, वन टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196 (मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच) के तहत रियाज के

खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कमिश्नर ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशानिर्देशों के तहत पोस्टमार्टम और जांच की गई है।

पुलिस के अनुसार, रियाज 2021 से तेलंगाना और महाराष्ट्र में चोरी, डकैती, झपटमारी, हत्या के प्रयास और एक हत्या सहित 61 आपराधिक मामलों में वांछित एक आदतन अपराधी था।

17 अक्टूबर की रात, रियाज को निजामाबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) के कांस्टेबल ई प्रमोद और एसआई विठ्ठल राव ने निजामाबाद में उसके घर से एक वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। जब वे रियाज को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, तो उसने अचानक प्रमोद को चाकू से कई बार वार कर दिया और भाग गया। प्रमोद को सरकारी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था।

दो दिन बाद, पुलिस टीम ने उसे बोधन-निजामाबाद रोड पर पुराने सीआरपीएफ ग्राउंड के पास देखा। पुलिस टीम को रियाज का पीछा करते देख, एक स्थानीय वेल्डर - सैयद आसिफ - ने उसे रोकने की कोशिश की। रियाज ने आसिफ पर चाकू से हमला कर उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट पहुंचाई। पुलिस ने रियाज को काबू कर लिया और उसे भी चोटें लगने के कारण इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

कमिश्नर ने बताया कि आसिफ की बांह की नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उसकी सर्जरी हुई। पूरी तरह ठीक होने में एक साल लग सकता है।

एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रियाज की मौत की जांच की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "BNSS के तहत, हिरासत में मौत की न्यायिक जांच अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट ने रियाज के परिवार सहित सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए। तीन डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। पोस्टमार्टम के बाद, शव रियाज के परिवार को सौंप दिया गया। उन्होंने उसकी मौत के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया।"

रियाज एक खतरनाक अपराधी था जिसने पुलिस पर भी हमला किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसने एक कांस्टेबल की हत्या कर दी थी और अस्पताल में भी उसने एक और कांस्टेबल से राइफल छीनने की कोशिश की, जिसके चलते उसे गोली मार दी गई। यह घटना पुलिस की सतर्कता और अपराधियों से निपटने के उनके तरीके को दर्शाती है। रियाज के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे, जो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। उसकी मौत के बाद, पुलिस ने कानून के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया है, जिसमें न्यायिक जांच और पोस्टमार्टम शामिल हैं। यह मामला कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों को भी रेखांकित करता है।

Hindu

NHRC member reviews investigation into hidden camera case at Apollo University

Vijaya Bharathi Sayani visits campus, meets students and officials, and calls for a transparent, time-bound probe into the privacy breach

<https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/nhrc-member-reviews-investigation-into-hidden-camera-case-at-apollo-university/article70189687.ece>

Published - October 22, 2025 06:17 pm IST - CHITTOOR

K. Umashanker

National Human Rights Commission member Vijaya Bharathi Sayani addressing the media in Chittoor on Wednesday.

National Human Rights Commission (NHRC) member Vijaya Bharathi Sayani on Wednesday inspected the Apollo University campus here and reviewed the progress of the investigation into the alleged installation of hidden cameras in a restroom meant for women students and faculty.

Speaking to the media, Ms. Sayani said the Commission had taken suo motu cognisance of the incident after it came to light through a section of the media in the second week of October. Terming it a serious violation of privacy and human rights, she said, "The police are investigating the case. The suspects were arrested and are now out on bail. The Commission has urged the police to carry out a transparent and time-bound probe to ensure that the culprits are brought to justice."

During her visit, Ms. Sayani interacted with the university management, faculty members, and police officials, reviewing the measures taken by the institution following the incident. Officials informed her that an internal grievance redressal committee had been constituted to address student-related issues.

Later, she held discussions with students, who reportedly expressed a sense of insecurity and alleged that their concerns were not being addressed promptly. Ms. Sayani assured them that she would submit her observations to the Commission and follow up on the matter.

Apollo University Vice-Chancellor Vinod Bhatt, Deputy Superintendent of Police (Chittoor) T. Sainath, and Circle Inspector Nithya Babu accompanied the NHRC member during the inspection.

Deccan Chronicle

NHRC Member Visits Chittoor Apollo University Over Hidden Camera Case Andhra Pradesh

<https://www.deccanchronicle.com/southern-states/andhra-pradesh/nhrc-member-visits-chittoor-apollo-university-over-hidden-camera-case-1911815>

DC Correspondent 22 October 2025 8:52 PM

A member of the National Human Rights Commission (NHRC) Vijaya Bharathi Sayani visited the Apollo University in Chittoor on Wednesday to review alleged installation of hidden cameras in the women's restroom on the campus

Nellore: A member of the National Human Rights Commission (NHRC) Vijaya Bharathi Sayani visited the Apollo University in Chittoor on Wednesday to review alleged installation of hidden cameras in the women's restroom on the campus. A student had noticed the camera in the first week of this month and alerted the management which, in turn, complained to the police. Speaking to media after the visit, the commission member said NHRC took up the case suo motu after learning about the incident through newspapers and TV channels, treating it as a serious violation of human rights. Sayani said police investigation is currently underway. While full details cannot be disclosed yet, the accused have been arrested and released on bail. She said she has asked police to conduct a transparent and speedy investigation and ensure that the culprits are brought to justice at the earliest. In this regard, the NHRC member held a review meeting with university officials, faculty and students. The university informed her that an internal committee has been formed in accordance with the institution's rules to address various issues. Following her interaction with students, Sayani said no fresh complaints or problems have been reported. Those present at the review meeting included Apollo University chairman, registrar Pothuraju, chief operating officer Naresh Reddy and senior police officers, including DSPs Jyothi and Harinath Reddy (Source : Deccan Chronicle)

The Mooknayak

Supreme Court Orders UP-Gujarat Govts to Pay Compensation to Discriminated Transgender Teacher, Mandates Inclusive Policy Overhaul

In a landmark verdict for LGBTQ+ rights, the bench slammed governmental "lethargy" and directed the formation of a committee to draft a comprehensive equal opportunity policy for transgender persons nationwide.

<https://en.themooknayak.com/lgbtq-news/supreme-court-orders-up-gujarat-govts-to-pay-compensation-to-discriminated-transgender-teacher-mandates-inclusive-policy-overhaul>

Geetha Sunil Pillai | Published on: 22 Oct 2025, 2:08 pm

New Delhi- The Supreme Court of India has issued a comprehensive set of directives to enforce the rights of transgender persons, condemning the "grossly apathetic attitude" and "administrative lethargy" exhibited by the Union and State governments. The verdict, spanning 176 pages, emerged from the case of Jane Kaushik, a transgender woman who faced discrimination and termination from two private schools, exposing the vast chasm between legislative promises and ground reality.

The bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan pulled no punches, stating that the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, and its corresponding 2020 Rules have been "brutishly reduced to dead letters." The Court expressed profound dismay that despite the law being in place for over half a decade, its implementation has been superficial or non-existent, leaving the transgender community in a state of continued marginalization.

"The lethargy exhibited on part of the concerned Government has also led the non-state establishments to put the compliance... in a cold freeze. This abeyance of rights is a matter of serious concern," the judgment observed.

Holding both private entities and the state accountable, the Court awarded compensation to petitioner Jane Kaushik. The Second School in Jamnagar, Gujarat, was directed to pay Rs. 50,000 for its discriminatory act of revoking a job offer after discovering her gender identity. Furthermore, in a significant move, the Court also held the governments responsible for their failure to create support systems. The States of Uttar Pradesh and Gujarat were each directed to pay Rs. 50,000 to Kaushik for their "inaction and lethargy which resulted in lack of redressal mechanisms."

The Background of the Case

In Writ Petition (Civil) No. 1405 of 2023, Jane Kaushik alleged wrongful dismissal from two private schools in different states due to her gender identity. Having graduated from Rajasthan in 2016, she completed a Nursery Teacher Training diploma in Haryana in 2017 and a postgraduate degree in Political Science from Gujarat in 2018. In 2019, she underwent gender-affirming surgery and enrolled in a B.Ed. program at a university in

Uttar Pradesh in 2020 to pursue her passion for teaching. In November 2022, she was selected as a Trained Graduate Teacher for English and Social Science at the first school (Respondent No. 5) in Uttar Pradesh.

However, after just eight days, she faced name-calling, harassment, and body-shaming from colleagues and students for not conforming to traditional female gender norms. Upon complaining to the principal on December 1, 2022, assurances were given, but on December 3, she was coerced into resigning after revealing her identity to a student. The school accepted the resignation citing poor performance in Social Science but later issued a Rs 1 crore defamation notice after media reports exposed her transgender identity.

At the second school (Respondent No. 4) in Jamnagar, Gujarat, she received an offer letter for an English teacher position on July 24, 2023, following video interviews. However, while en route, calls demanding identity proofs led to her denial of entry upon revelation of her transgender status. The school claimed it was an administrative decision based on comparing candidates' merits, but the court deemed it discrimination on gender identity grounds.

The bench noted that Section 9 explicitly prohibits discrimination even in recruitment. Prior to approaching the Supreme Court, Kaushik sought redress from the National Commission for Women (NCW), National Human Rights Commission (NHRC), and National Council for Transgender Persons (NCTP), but received no relief. The court viewed this as a failure of the grievance redressal mechanisms under the 2019 Act.

A Blueprint for Substantive Equality and Reasonable Accommodation

In the judgment, the bench expressed profound sorrow over the transgender community's plight. The court stated, "It has been more than half a decade since the Transgender Persons (Protection of Rights Act), 2019... However, the reality is that these rights remain only an empty formality." Referencing the NALSA (2014) judgment, it emphasized recognition of transgender persons as the 'Third Gender' with rights to equality and dignity, yet lamented the state's and private institutions' lethargy in implementation. The bench underscored reasonable accommodation as integral to substantive equality, declaring it a positive obligation beyond mere negative prohibitions, essential for mainstream integration of transgender individuals.

The bench also addressed 'omission' in discrimination law as discriminatory itself. Drawing on Sandra Fredman's four-dimensional framework, it outlined equality as redressing disadvantage, confronting stigma and stereotypes, enhancing voice and participation, and accommodating differences for structural change. The court remarked, "The transgender community faces problems ranging from social exclusion to discrimination, lack of educational facilities, unemployment, lack of medical facilities and so on." Criticizing the 2019 Act for diluting self-determination rights as envisioned in NALSA, the bench highlighted its over-reliance on medicalization. It bolstered the concept with precedents from Canada, the US, and the EU.

A pivotal section of the verdict critiques the 2019 Act's deficiencies. The bench noted the absence of effective grievance mechanisms, leaving transgender individuals vulnerable. Only 11 states have established Transgender Protection Cells, and most have not framed rules. On employment discrimination, it observed, "Transgender persons routinely face multiple forms of oppression, social exclusion and discrimination, especially in the field of... employment." The court supported indirect horizontal application of fundamental rights to private entities via the Act.

Acting under Article 142 of the Constitution, the Supreme Court issued a series of binding directives, providing a three-month deadline for compliance. These mandates include: The establishment of a Transgender Protection Cell in every district under the District Magistrate and at the state level under the Director General of Police. The mandatory designation of a Complaint Officer in every "establishment", which includes private companies, schools, and hospitals, to address grievances filed by transgender persons. A requirement for all state governments to constitute a Welfare Board for transgender persons. The setup of a dedicated, nationwide toll-free helpline to report violations of the Act.

Stringent Directives for Immediate Compliance

To translate these principles into action, the Supreme Court issued a series of binding directives under Article 142 of the Constitution, giving the Union and States a three-month deadline for compliance.

Acknowledging the complex, multi-faceted nature of the issue, the Court constituted an 8-member Advisory Committee, chaired by former Delhi High Court Judge Justice Asha Menon, to draft a comprehensive equal opportunity policy and suggest legislative improvements. The committee, which includes prominent transgender rights activists like Akkai Padmashali and Grace Banu, as well as legal and medical experts, has been given a six-month timeline to submit its report. The Union of India is then expected to formulate its final policy within three months of receiving the committee's recommendations. The Court has initially sanctioned Rs. 10 lakh for the committee's operations.

The judgment also provided "meaningful suggestions" to foster a more inclusive environment. It recommended the creation of gender-neutral washrooms in all public and private establishments, updating all application forms to include a 'Third Gender' option, and sensitizing security personnel at airports and other public spaces. It urged educational bodies like the UGC and CBSE to adopt inclusive policies respecting students' self-identified gender. The Court also suggested that the National Medical Commission revamp its curriculum to include training on gender-affirming care.

In a scathing conclusion, the Court emphasized the state's constitutional obligation, stating, "The promise of equality under the Constitution is not a passive assurance but an active obligation, one that demands continuous vigilance and affirmative measures."

By placing the issue under a continuing mandamus, the Supreme Court has ensured that its directives will be monitored, signaling a firm resolve to bridge the gap between law and life for India's transgender community.

Awaaz India Tv

ट्रांसजेंडर कानून पर सरकारों के 'घोर उदासीन रवैये' की सुप्रीम कोर्ट ने की आलोचना, भेदभाव की शिकार शिक्षिका को मुआवज़े का दिया आदेश

<https://awaazindiatv.com/?p=8287>

October 22, 2025

By Admin - 8 hours ago

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में जेंडर पहचान के कारण दो स्कूलों से नौकरी से निकाली गई ट्रांसजेंडर शिक्षिका जेन कौशिक को मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, २०१९ को लागू करने में "उदासीन रवैये" के लिए आलोचना की है और एक सलाहकार समिति भी गठित की है। यह समिति ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समान अवसर की नीतियां बनाने में मदद करेगी।

जेन कौशिक नामक एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका को गुजरात और उत्तर प्रदेश के दो निजी स्कूलों से उनकी जेंडर पहचान के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन वे केवल छह दिन ही पढ़ा सकीं, जबकि गुजरात में उन्हें शामिल ही नहीं होने दिया गया।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने १७ अक्टूबर, २०२५ को एक ऐतिहासिक फैसले में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, २०१९ को लागू करने में "घोर उदासीन रवैये" और "सुस्ती" के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह माना कि एक कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने में विफलता "चूक द्वारा भेदभाव" के समान है।

अदालत ने याचिकाकर्ता, सुश्री जेन कौशिक, को उनके साथ हुए भेदभाव और राज्य द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफलता के लिए मुआवज़ा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही, न्यायालय ने २०१९ के अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई अनिवार्य और समयबद्ध निर्देश जारी किए और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक व्यापक समान अवसर नीति तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, सुश्री जेन कौशिक, एक ट्रांसजेंडर महिला हैं, जिन्हें एक साल के भीतर दो अलग-अलग निजी स्कूलों से नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद ३२ के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी पहली नौकरी नवंबर २०२२ में "पहले स्कूल" (प्रतिवादी संख्या ५) में एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने आठ दिनों के कार्यकाल के दौरान, उन्हें "नाम-चिढ़ाने, उत्पीड़न और शारीरिक शर्मिंदगी" का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने एक छात्र के सामने अपनी ट्रांसजेंडर पहचान उजागर की, तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें वेतन रोकने की धमकी देकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि, स्कूल ने उनकी बर्खास्तगी का कारण "खराब प्रदर्शन" बताया। सुश्री

कौशिक को नौकरी का दूसरा अवसर गुजरात के “दूसरे स्कूल” (प्रतिवादी संख्या 4) में मिला, जिसने उन्हें जुलाई जुलाई २०२३ में एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में पद की पेशकश की। हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह नौकरी ज्वाइन करने के लिए यात्रा कर रही थीं, तब स्कूल अधिकारियों को उनके ट्रांसजेंडर होने का पता चला और उन्होंने उन्हें नौकरी देने तथा स्कूल परिसर में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। स्कूल ने तर्क दिया कि प्रस्ताव पत्र रोजगार की गारंटी नहीं देता और यह निर्णय एक “प्रशासनिक कार्रवाई” थी।

सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, सुश्री कौशिक ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (NCTP), और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सहित विभिन्न निकायों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई प्रभावी राहत नहीं मिली। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच समिति ने यह निष्कर्ष निकालते हुए जांच जांच बंद कर दी थी कि पहले स्कूल के खिलाफ “भेदभाव का कोई मामला नहीं बनता है।”

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक समान अवसर नीति का मसौदा तैयार करेगी कमेटी

फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा २०१९ एक्ट की कमियों पर केंद्रित है। बेंच ने कहा कि एक्ट में शिकायत निवारण तंत्र की कमी ने ट्रांसजेंडर को असहाय बना दिया है। कोर्ट ने नोट किया कि केवल ११ राज्यों में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बने हैं और अधिकांश राज्यों ने नियम नहीं बनाए। रोजगार में भेदभाव के मामलों का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा, “ट्रांसजेंडर को कार्यस्थलों पर पूर्वाग्रहपूर्ण सामाजिक मानदंडों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।” कोर्ट ने अप्रत्यक्ष क्षैतिज अनुप्रयोग के माध्यम से निजी संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का समर्थन किया। ट्रांसजेंडर समुदाय की दैनिक चुनौतियों पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। निगरानी, हाइपर-विजिलेंस, रोजगार में प्रवेश बाधाएं, पहचान दस्तावेजों में बदलाव की कठिनाई, शैक्षणिक बहिष्कार और सामाजिक-राजनीतिक बहिष्कार का जिक्र किया। विभिन्न हाईकोर्ट फैसलों का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि ट्रांसजेंडर को पुलिस उत्पीड़न, चिकित्सा जांचों में अपमान और पेंशन लाभों से वंचित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने सुझाव दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम, जागरूकता अभियान और चिकित्सा पाठ्यक्रम में सुधार आवश्यक हैं।

फैसले में कोर्ट ने अनुच्छेद १४२ के तहत कई निर्देश जारी किए। सभी राज्यों में अपीलीय प्राधिकारी, वेलफेयर बोर्ड और प्रोटेक्शन सेल गठित करने का आदेश दिया। हर संस्थान में शिकायत अधिकारी नियुक्ति अनिवार्य की। राज्य मानवाधिकार आयोग को अपील फोरम बनाया। राष्ट्रव्यापी टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, “ये निर्देश अनिवार्य हैं और तीन महीने में पालन सुनिश्चित किया जाए।”

ट्रांसजेंडर मुद्दों पर गहन अध्ययन के लिए एक सलाहकार समिति गठित की, जिसमें जस्टिस आशा मेनन (रिटायर्ड) को चेयरपर्सन बनाया। समिति में एक्टिविस्ट अक्काई पद्माशाली, ग्रेस बानू, व्यजयंती वसंत मोगली जैसे सदस्य हैं। एक्स-ऑफिशियो सदस्यों में सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव शामिल। समिति को छह महीने में समान अवसर नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य सौंपा। कोर्ट ने कहा, “यह समिति ट्रांसजेंडर अधिकारों को मजबूत करने के लिए नीतिगत सिफारिशें देगी।” समिति की सिफारिशें मिलने के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार से अपनी अंतिम नीति बनाने की उम्मीद है। अदालत ने शुरुआती कार्यों के लिए समिति को 10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

यह फैसला न केवल जेन कौशिक को न्याय देता है, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई उम्मीद जगाता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि राज्य की सुस्ती से अधिकार खोखले हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ट्रांसजेंडर समावेशन को तेज करेगा और 2019 एक्ट को मजबूत बनाएगा। यूनियन को तीन महीने में अपनी नीति लाने का आदेश है, जबकि मामला कंटीन्यूइंग मेंडामस के तहत चलेगा। यह फैसला भारतीय संविधान की समानता की भावना को मजबूत करता है, जहां ट्रांसजेंडर भी मुख्यधारा का हिस्सा बनें।

The Mooknayak

ट्रांसजेंडर टीचर के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: यूपी-गुजरात की सरकारें देंगी मुआवजा, बनाई जाएगी समावेशी नीति

शीर्ष अदालत ने एक व्यापक समान अवसर नीति का मसौदा तैयार करने और विधायी सुधारों का सुझाव देने के लिए पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में 8-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति में अक्कई पद्मशाली और ग्रेस बानू जैसी प्रमुख ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता, साथ ही कानूनी और चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। समिति की सिफारिशें मिलने के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार से अपनी अंतिम नीति बनाने की उम्मीद है। अदालत ने शुरुआती कार्यों के लिए समिति को 10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

<https://www.themooknayak.com/lgbtq-news/supreme-court-orders-compensation-for-discriminated-transgender-teacher-mandates-inclusive-policy-overhaul>

जेन कौशिक को गुजरात के जामनगर में 24 जुलाई 2023 को इंग्लिश टीचर के लिए ऑफर लेटर मिला, लेकिन यात्रा के दौरान पहचान दस्तावेज साझा करने पर उन्हें प्रवेश ही नहीं दिया गया। इससे पूर्व नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के एक स्कूल ने उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया।

Geetha Sunil Pillai | Published on: 22 Oct 2025, 12:32 pm

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने वाले एक 177 पेज के लम्बे और ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर याचिकाकर्ता जेन कौशिक को दो निजी स्कूलों द्वारा भेदभावपूर्ण बर्खास्तगी के मामले में न्याय प्रदान किया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यूपी और गुजरात राज्यों को कौशिक को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, बल्कि जामनगर के स्कूल को भी ट्रांसजेंडर टीचर को 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश जारी किया।

कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 की कमियों पर गहरी चिंता जताते हुए एक सलाहकार समिति गठित करने और समावेशी रोजगार-शिक्षा नीति बनाने का आदेश दिया है। इस फैसले को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक मील का पत्थर साबित होने की आशा की जा रही है, जो लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार और संस्थागत भेदभाव का शिकार रहा है।

ये है पूरा मामला

याचिका (सिविल) नंबर 1405/2023 में जेन कौशिक ने दो अलग-अलग राज्यों के निजी स्कूलों में नौकरी से बर्खास्तगी का आरोप लगाया था। 2016 में राजस्थान से स्नातक करने वाली जेन ने 2017 में हरियाणा से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और 2018 में गुजरात से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। 2019 में उन्होंने जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी कराई और 2020 में उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई पूरी की। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के पहले स्कूल (रिस्पॉन्डेंट नंबर 5) में इंग्लिश और सोशल साइंस टीचर के रूप में चयनित हुईं, लेकिन केवल आठ दिनों बाद ही सहकर्मियों और छात्रों द्वारा नाम-कॉलिंग, उत्पीड़न और बॉडी शेमिंग का शिकार हुईं। स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत करने पर आश्वासन तो मिला, लेकिन 3 दिसंबर 2022 को उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। स्कूल ने इस्तीफे को स्वीकार

करते हुए खराब प्रदर्शन का हवाला दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रांसजेंडर पहचान का खुलासा होने के बाद 1 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा।

दूसरे स्कूल (रिस्पॉन्डेंट नंबर 4) गुजरात के जामनगर में 24 जुलाई 2023 को इंग्लिश टीचर के लिए ऑफर लेटर मिला, लेकिन यात्रा के दौरान पहचान दस्तावेज साझा करने पर उन्हें प्रवेश ही नहीं दिया गया। स्कूल ने दावा किया कि यह प्रशासनिक निर्णय था और अन्य उम्मीदवारों की तुलना के बाद लिया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे ट्रांसजेंडर पहचान पर आधारित भेदभाव माना। बेंच ने कहा कि सेक्शन 9 स्पष्ट रूप से भर्ती में भेदभाव निषेध करता है। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (एनसीटीपी) जैसे मंचों पर शिकायत की, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। कोर्ट ने इसे 2019 एक्ट के तहत शिकायत निवारण तंत्र की विफलता का प्रमाण माना।

कोर्ट की फटकार- बेअसर कर दिया नालसा जजमेंट

फैसले में बेंच ने ट्रांसजेंडर समुदाय की दयनीय स्थिति पर गहरा शोक व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा, "यह अधिक से अधिक आधा दशक हो गया है जब ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 लागू हुआ... लेकिन वास्तविकता यह है कि ये अधिकार केवल खोखली औपचारिकता बने हुए हैं।" बेंच ने नालसा (2014) फैसले का हवाला देते हुए जोर दिया कि ट्रांसजेंडर को 'थर्ड जेंडर' मानते हुए समानता और गरिमा का अधिकार दिया गया था, लेकिन राज्य और निजी संस्थाओं की सुस्ती ने इसे बेअसर कर दिया। कोर्ट ने रीजनेबल एक्कॉमोडेशन को सबस्टेंटिव इकालिटी का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह नकारात्मक प्रतिबंध से आगे बढ़कर सकारात्मक दायित्व है, जो ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए आवश्यक है।

बेंच ने भेदभाव कानून में 'ओमिशन' (चूक) को भी भेदभाव का रूप माना। संड्रा फ्रेडमैन के चार-आयामी दृष्टिकोण का सहारा लेते हुए कोर्ट ने कहा कि समानता का मतलब नुकसान की भरपाई, कलंक-रूढ़ियों का सामना, आवाज और भागीदारी बढ़ाना तथा संरचनात्मक बदलाव लाना है। कोर्ट ने टिप्पणी की, "ट्रांसजेंडर समुदाय सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना कर रहा है।" 2019 एक्ट की आलोचना करते हुए बेंच ने कहा कि यह आत्म-निर्धारण के अधिकार को कमजोर करता है और चिकित्सकीय हस्तक्षेप पर निर्भर बनाता है। कोर्ट ने कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के उदाहरणों से रीजनेबल एक्कॉमोडेशन को मजबूत किया।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए "उचित आवास" की अवधारणा पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि यह कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। "कानून के समान संरक्षण का वादा उचित आवास के वादे को भी सुनिश्चित करेगा... समानता का मतलब केवल तभी समान व्यवहार होगा जब परिस्थितियाँ समान हों। समान परिस्थितियों के अभाव में, सकारात्मक भेदभाव का नियम समानता की अवधारणा में निहित है।"

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक समान अवसर नीति का मसौदा तैयार करेगी कमेटी, 10 लाख रुपये स्वीकृत

फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 2019 एक्ट की कमियों पर केंद्रित है। बेंच ने कहा कि एक्ट में शिकायत निवारण तंत्र की कमी ने ट्रांसजेंडर को असहाय बना दिया है। कोर्ट ने नोट किया कि केवल 11 राज्यों में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बने हैं और अधिकांश राज्यों ने नियम नहीं बनाए। रोजगार में भेदभाव के मामलों

का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा, "ट्रांसजेंडर को कार्यस्थलों पर पूर्वाग्रहपूर्ण सामाजिक मानदंडों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।" कोर्ट ने अप्रत्यक्ष क्षैतिज अनुप्रयोग के माध्यम से निजी संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का समर्थन किया।

ट्रांसजेंडर समुदाय की दैनिक चुनौतियों पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। निगरानी, हाइपर-विजिलेंस, रोजगार में प्रवेश बाधाएं, पहचान दस्तावेजों में बदलाव की कठिनाई, शैक्षणिक बहिष्कार और सामाजिक-राजनीतिक बहिष्कार का जिक्र किया। विभिन्न हाईकोर्ट फैसलों का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि ट्रांसजेंडर को पुलिस उत्पीड़न, चिकित्सा जांचों में अपमान और पेंशन लाभों से वंचित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने सुझाव दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम, जागरूकता अभियान और चिकित्सा पाठ्यक्रम में सुधार आवश्यक हैं।

फैसले में कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत कई निर्देश जारी किए। सभी राज्यों में अपीलीय प्राधिकारी, वेलफेयर बोर्ड और प्रोटेक्शन सेल गठित करने का आदेश दिया। हर संस्थान में शिकायत अधिकारी नियुक्ति अनिवार्य की। राज्य मानवाधिकार आयोग को अपील फोरम बनाया। राष्ट्रव्यापी टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, "ये निर्देश अनिवार्य हैं और तीन महीने में पालन सुनिश्चित किया जाए।"

ट्रांसजेंडर मुद्दों पर गहन अध्ययन के लिए एक सलाहकार समिति गठित की, जिसमें जस्टिस आशा मेनन (रिटायर्ड) को चेयरपर्सन बनाया। समिति में एक्टिविस्ट अक्काई पद्माशाली, ग्रेस बानू, व्यजयंती वसंत मोगली जैसे सदस्य हैं। एक्स-ऑफिशियो सदस्यों में सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव शामिल। समिति को छह महीने में समान अवसर नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य सौंपा। कोर्ट ने कहा, "यह समिति ट्रांसजेंडर अधिकारों को मजबूत करने के लिए नीतिगत सिफारिशें देगी।" समिति की सिफारिशें मिलने के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार से अपनी अंतिम नीति बनाने की उम्मीद है। अदालत ने शुरुआती कार्यों के लिए समिति को 10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

यह फैसला न केवल जेन कौशिक को न्याय देता है, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई उम्मीद जगाता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि राज्य की सुस्ती से अधिकार खोखले हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ट्रांसजेंडर समावेशन को तेज करेगा और 2019 एक्ट को मजबूत बनाएगा। यूनियन को तीन महीने में अपनी नीति लाने का आदेश है, जबकि मामला कंटीन्यूइंग मेंडामस के तहत चलेगा। यह फैसला भारतीय संविधान की समानता की भावना को मजबूत करता है, जहां ट्रांसजेंडर भी मुख्यधारा का हिस्सा बनें।

Summary

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अनुपालन के लिए तीन महीने की समयसीमा देते हुए बाध्यकारी निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की। इसमें जिला मजिस्ट्रेट के अधीन प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक के अधीन एक ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल की स्थापना शामिल है। हर "प्रतिष्ठान", जिसमें निजी कंपनियाँ, स्कूल और अस्पताल शामिल हैं, को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत अधिकारी नामित करना होगा। इसके अलावा, सभी राज्यों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन करना होगा और अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित देशव्यापी टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित करनी होगी।

Times of India

Protests over the plight of 127 tribal girl students at Thirunelli Ashram School

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/protests-over-the-plight-of-127-tribal-girl-students-at-thirunelli-ashram-school/articleshow/124746884.cms>

TNN | Oct 23, 2025, 12.12 AM IST

Kozhikode: Opposition youth and student organisations staged protests before the ITDP office in Mananthavady, Wayanad, on Wednesday over the plight of 127 tribal girl students of Govt Ashram School at Thirunelli.

The students were forced to stay in just three classrooms after the girls' hostel was declared unfit by PWD department in July. They were also relying on a single bathroom to meet their basic needs.

Youth Congress and Yuva Morcha activists led the protests, while KSU workers wrote to National Human Rights Commission highlighting the issue.

State scheduled tribe development department planned to shift the school to the new Model Residential School in Aralam, Kannur. However, the move was not implemented due to delays in obtaining a power connection.

Congress alleged that relocating the school outside the district despite available facilities locally is highly questionable and that there is little chance of the institution returning to Wayanad, which has the highest tribal population in state.

KPCC general secretary K L Poullose said it is a disgrace that the incident happened in the constituency of tribal development minister O R Kelu and demanded intervention by state human rights commission and child rights commission on the matter.

Swar Vidroh Times

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने की विभागीय लापरवाही द्वारा घटित घटना की न्यायिक जाँच की मांग !

<https://swarvidrohtimes.com/archives/6028>

By Swar Vidroh Times | October 22, 2025

झारखण्ड : साहेबगंज

22 अक्टूबर 2025 : “राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन” के झारखण्ड प्रदेश महासचिव बसंत कुमार महतो ने पत्र जारी कर बीते रविवार दिनांक 19/10/25 झारखण्ड के गोड्डा जिले के थाना सुन्दरपहाड़ी के गांव डाहुबेडा में विभागीय द्वारा निर्मित पानी की टंकी के भरभरा कर गिरने से टंकी के नीचे स्नान कर रहे आदिमजनजाति के दो बच्चों की आकस्मिक मौत और तीन के गंभीर रूप से घायल होने की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक एवं भयावह थी को लेकर जिले के उपायुक्त महोदय, जिले के आरक्षी अधीक्षक महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राजयपाल महोदय, राज्य मानवाधिकार आयोग, रांची, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, दिल्ली के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायलय, झारखण्ड, रांची को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर विभागीय लापरवाही द्वारा घटित घटना की न्यायिक जाँच कर दोषियों को चिन्हित कर उन्हें दण्डित करने साथ ही उक्त घटना में मृत एवं घायल बच्चों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है, प्रदेश महासचिव बसंत कुमार का कहना है कि संगठन जमीनी स्तर पर गरीब, बेसहारा एवं प्रताड़ितों को शासन प्रशासन की मदद से उन्हें न्याय दिलाने का काम करती है, साथ ही शासन स्तर से यदि मानवाधिकार का हनन होता है तो संगठन एक आवाज बन कर उनका साथ देती है, डाहुबेडा में घटित घटना पर संगठन परिवार अंतर्मन से दुःख प्रकट करती है, घटना में मृत बच्चों की आत्मा को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती है साथ ही घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ शुभ मंगल की कामना करती है।

स्टेट को-ऑर्डिनेटर झारखण्ड बसंत कुमार महतो की रिपोर्ट